

केन्द्रीय आम बजट : 2019-20

देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई, 2019 को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए 27 लाख 86 हजार 349 करोड़ रुपये का केन्द्रीय आम बजट प्रस्तुत किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट था। पहली बार बजट को बहीखाता नाम दिया गया है। बुनियादी ढाँचे का विकास, भारत का 5000 अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना, किसान कल्याण और जल सुरक्षा इस बजट की मुख्य बातें हैं।

केन्द्रीय बजट 2019-20 : परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण बिन्दु

- भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष में \$3 ट्रिलियन हो जाने का अनुमान है। वर्तमान में भारत छठी बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति समता की दृष्टि से यह अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- बजट में चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 3.6 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है।
- व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई परिवर्तन इस बजट में नहीं किया गया है एवं 5 लाख रुपये तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी।
- लोग पैन की जगह आधार से भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे।
- 45 लाख रुपये तक का घर खरीदने पर 31 मार्च, 2020 तक की अवधि हेतु 1.5 लाख की अतिरिक्त टैक्स छूट दी जायेगी। 15 साल की ऋण अवधि पर लगभग 7 लाख रुपये का लाभ होगा।
- बैंक खाते से सालाना 1 करोड़ से अधिक की नकदी निकासी पर 2% TDS लगेगा।
- 2-5 करोड़ सलाना आय वालों को 3% अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा।
- 5 करोड़ से ज्यादा सलाना आय वालों पर 7% अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा।
- प्रत्यक्ष कर 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 11.37 लाख करोड़ हुआ।
- 400 करोड़ रुपये की टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25% कॉरपोरेट टैक्स लगेगा। यानी 99.3 प्रतिशत कंपनियाँ इस दायरे में आ जाएँगी।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख का अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगा।
- आम नागरिकों के इस्तेमाल के लिए जल्द ही 1, 2, 5, 10 और 20 रुपये के नये सिक्के जारी किए जायेंगे।
- ऋण क्षमता बढ़ाने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाएँगे।
- 1.5 करोड़ रुपये से कम कारोबार वाले देश की 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।
- स्फूर्ति के अंतर्गत 100 नए क्लस्टर बनाये जाएँगे। इससे 50,000 हजार दस्तकार आर्थिक मूल्य श्रृंखला से जुड़ सकेंगे।
- NPA पिछले साल 1 लाख करोड़ था। IBC और अन्य कदमों के चलते 4 लाख करोड़ NPA की वसूली हुई।
- अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं होगी।
- उज्ज्वला योजना के तहत 35 करोड़ LED बल्ब बांटे गए, जिससे 18341 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई।
- अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 'नारी नू नारायणी' नाम से समिति बनाने का प्रस्ताव।
- जनधन खाता वाले स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य को 5000 रुपये की ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दी जायेगी।
- स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक महिला मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ऋण लेने के लिए पात्र होगी।
- स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत महिलाओं, एससी/एसटी उद्यमियों को मदद की जायेगी।
- 2022 तक गांव के हर परिवार के पास बिजली और एलपीजी कनेक्शन।
- मीडिया, एविएशन जैसे क्षेत्रों में FDI निवेश बढ़ाने पर विचार।
- भारत में सालाना ग्लोबल इनवेस्टमेंट मीट का आयोजन किया जायेगा।
- जीएसटी पंजीकृत अति लघु, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को ब्याज में दो प्रतिशत की छूट के लिए के लिए 350 करोड़ का आवंटन।
- 97% लोगों को हर मौसम में मिलेगी सड़क।
- शिक्षा क्षेत्र हेतु 94,853 करोड़ रुपये आवंटित।
- विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थानों के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रों के लिए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम।
- स्कूली एवं उच्च शिक्षा में बदलाव करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनेगी।
- बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए बजट में 368.20 करोड़ रुपये रखा गया है।
- रक्षा क्षेत्र हेतु 3.18 लाख करोड़ रुपये आवंटित। आवंटित कुल राशि में से 1,08,248 करोड़ नये हथियारों, प्लेटफॉर्मों और सैन्य हार्डवेयर की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय हेतु निर्धारित किए गये हैं।
- नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, ताकि रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। रिसर्च सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
- खेलो इंडिया स्कीम का विस्तार किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित किया जायेगा।
- स्टार्टअप के लिए नए चैनल शुरू करने की योजना। स्टार्टअप के लिए डीडी के चैनलों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जायेगा।
- कृषि क्षेत्र हेतु 1,51,518 लाख करोड़ रुपये आवंटित।
- प्रधानमंत्री किसान योजना हेतु 75000 करोड़ रुपये आवंटित।
- अन्नदाता (किसान) को ऊर्जादाता बनाने के कार्यक्रम तैयार किए जाएँगे।
- अगले 5 वर्षों में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएँगे।
- जीरो बजट फार्मिंग के जरिए किसानों की आमदनी दोगुनी करने का प्रस्ताव दिया गया है।

- इज ऑफ डूइंग बिजनेस और इज ऑफ लिविंग किसानों पर लागू होगी।
- मत्स्यपालन को कृषि में शामिल किया गया है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु बजट में 62,659 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 6400 करोड़ आवंटित किया गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत लगभग 81 लाख घरों के निर्माण के लिए 4.8 लाख करोड़ रुपये की निवेश को मंजूरी दी गई। इनमें 47 लाख घरों का निर्माण कार्य शुरू हुआ।
- 95 प्रतिशत से अधिक शहरों को भी खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया।
- 2 अक्टूबर, 2019 को गांधी दर्शन में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा।
- लगभग 30 लाख कामगार प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना में शामिल हो गये हैं।
- पीपीपी को प्रोत्साहित करने और तेजी से पूरा करने के लिए मेट्रो रेल की पहल को बढ़ाया जायेगा।
- देश में 657 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया है।
- नया जलशक्ति मंत्रालय एक समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन की देखरेख करेगा।
- 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति की जाएगी।
- जलशक्ति अभियान के लिए 256 जिलों के 1592 खंडों की पहचान की गई है।
- अब तक 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- 5.6 लाख से अधिक गाँवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है।
- 2 अक्टूबर, 2019 को भारत खुले में शौच से मुक्त हो जायेगा।
- 2 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को डिजिटली रूप से साक्षर बनाया गया।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत, अगले पांच वर्षों में 1.25 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जायेगा। परियोजना लागत 80,200 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित है।
- अगले पाँच सालों में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तकनीक का इस्तेमाल कर कार्बन मुक्त बनाया जायेगा।
- सरकार वर्ष 2022 तक 1.95 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करायेगी। पिछले 5 साल में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराये गये। इससे पहले 2016-16 में जहाँ ऐसे मकान बनाने में 314 दिन लगते थे, वर्ष 2017-18 में यह घटकर 114 दिन रह गया है।
- अगले 5 वर्ष में बुनियादी ढांचा में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जायेगा।
- सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिये विनिवेश के जरिये 1,05,000 करोड़ रूपए प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले तीन साल के दौरान गिरावट आने के बावजूद भारत में 6 प्रतिशत बढ़कर 64 अरब डॉलर से अधिक रहा है।
- इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंडों में ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई और एडीआई द्वारा निवेश की अनुमति दी जायेगी। सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी 25% से बढ़ाकर 35% की जा सकती है।

- एक कंपनी में FPI पर सीमा 24% तक बढ़ गई।
- पूंजी और इक्विटी और ऋण जुटाने के लिए सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों के लिए एक सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज प्रस्तावित है।
- बीमा बिचौलियों के लिए 100% एफडीआई। एकल-बॉन्ड के रिटेल क्षेत्र में एफडीआई के लिए स्थानीय सोर्सिंग मानदंड आसान किए जाएंगे।
- 17 करों (Tax) और 13 उपकरों (Cesses) जीएसटी के तहत एक टैक्स बन गए हैं।
- सरकार एमएसएमई को बिलों का भुगतान करने और समय बचाने में सक्षम बनाने के लिए एक भुगतान मंच बनाएगी।
- सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का पुनर्गठन करेगी। भारतमाला के दूसरे चरण में, राज्य राजमार्गों को विकसित करने में राज्यों की मदद की जाएगी।
- रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण के लिए एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- बजट में रेलवे हेतु 65,837 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है।
- 2018 और 2030 के बीच रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए 50 लाख करोड़ रु. के निवेश की आवश्यकता होगी, जिसके लिए पीपीपी मॉडल तैयार किया जायेगा, जोकि तेजी से विकास और यात्री माल सेवाओं के वितरण में मदद के लिए होगा।
- उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए मसौदा कानून इस वर्ष के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कौशल विकास योजना के तहत 10 मिलियन युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सोना और अन्य कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया है।
- पेट्रोल और डीजल के दाम में 1 रुपये प्रति लीटर की दर से बढ़ाया गया है।

केंद्र सरकार का व्यय

2019-20 के लिए बजट अनुमान (₹ करोड़ में)

मद	मद
पेंशन 1,74,300	ब्याज 6,60,471
रक्षा 3,05,296	आईटी और दूरसंचार 21,783
प्रमुख सब्सिडी 3,01,694	योजना एवं सांख्यिकी 5,814
कृषि और संयुक्त कार्यकलाप 1,51,518	ग्रामीण विकास 1,40,762
वाणिज्य और उद्योग 27,043	वैज्ञानिक विभाग 27,431
पूर्वोत्तर का विकास 3,000	सामाजिक कल्याण 50,850
शिक्षा 94,854	कर प्रशासन 1,17,285
ऊर्जा 44,638	राज्यों को अंतरण 1,55,447
विदेश मामले 17,885	परिवहन 1,57,437
वित्त 20,121	संघ राज्य क्षेत्र 15,098
स्वास्थ्य 64,999	शहरी विकास 48,032
गृह 1,03,927	अन्य 76,665
	कुल जोड़ 27,86,349

© PIB/KBK